हर काम के दाम तय है

सिविल अस्पताल में इलाज कम रिश्वतखोरी ज्यादा

पलवल : सिविल अस्पताल में रिश्वत और लापरवाही का खेल दशकों पुराना है। हड्डी तोड़कर फर्जी एमएलआर काटने से लेकर ऑपरेशन करने तक में रिश्वत हावी है। ऑपरेशन हाथ की जगह पैर का करना है या फिर ऑखों में लैंस डालने का। अस्पताल के लिए कुर्सी, मेज और दवाईयों से लेकर, कांट्रेक्टर स्तर पर नौकरी लगाना या फिर सफाई के लिए क्लीनर खरीदने, ऑक्सीजन प्लांट के पाइप खरीदने, चादर धुलाई में कमीशन का खेल है। वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट बनवाने, फिटनेस मेडिकल तक रिश्वत के दम पर बनाए जा रहे हैं। आक्सिट्रेटरों की खरीद से लेकर इलेक्ट्रोनिक का सामान खरीद में भी रिश्वत का लेन-देन है। महिलाओं की डिलीवरी, मरीजों को रेफर करना और रेप पीड़ित महिला की सस्पेक्टिड़ रिर्पोट बनाने तक में रिश्वत ली जा रही है। पोस्टमार्टम रिर्पोट बदलने और पोस्टमार्टम के लिए बाहर भेजने तक में रुपया चल रहा है। रिश्वत के इस खेल में डाक्टरों की जगह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बड़े मोहरे हैं।

गांव घोडी निवासी 20 वर्षीय प्रिंस के हाथ की जगह पैर का ऑपरेशन कर दिया और गलत ऑपरेशन के बदले 4 हजार रुपये भी ले लिए। हाथ की जगह पैर का ऑपरेशन और रिश्वत लेने का मामले को

सड़क दुर्घटना में प्रिंस का टूटा हाथ, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया टांग का

तूल पकडता देख सीएमओ डॉ.लोकवीर सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया। ऑपरेशन व रिश्वत लेने के दोनों मामलों की कमेटी जांच करेगी और जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। डाक्टरों की जांच कमेटी एक डाक्टर के खिलाफ सही रिर्पोट देगी भी या नहीं इसे लेकर भी संदेहे हैं। सिविल अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने डॉक्टर संदीप सोनी पर रिश्वत लेने के कई और आरोप लगाए हैं। इससे पहले डॉक्टर नवीन पर भी रिश्वत लेने के आरोप लगते रहे हैं। डाक्टर नवीन के खिलाफ जांच कमेटी बनाई गई लेकिन कुछ नहीं हुआ।

सीएमओ डॉ.लोकवीर सिंह के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के अध्यक्ष सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉ.अजय माम होंगे और इसमें इंडियन मेडिकल एसोशिएसन का सदस्य, आयुर्वेदिक डॉक्टर सहित पांच डॉक्टरों की जांच कमेटी का गठन किया गया है। जांच कमेटी एक सप्ताह के अंदर मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई कब अमल में लाई जाएगी इसे लेकर पीडित के मन में संशय है। सिविल अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदार चंद्रवती, सुनीता, सुल्तान व साजिदा ने बताया कि उनसे भी ऑपरेशन के नाम पर रिश्वत ली गई है। यह रिश्वत फोर्थ क्लास कर्मचारियों के माध्यम से ली गई है।

उन्होंने बताया कि मरीज ऑप्रेशन थियेटर में ले जाने के दौरान ऑपरेशन से जुड़ी दवाइयां व अन्य सामान की लंबी लिस्ट थमा दी जाती है। तीमारदार से सामान को लाने का दबाब बनाया जाता है या फिर इसके बदले पैसे मांगे जाते हैं। तीमारदार को दवाइयों व अन्य सामान की कीमत भी अधिक बताई जाती है। ऐसे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सामान उपलब्ध कराने के नाम पर पैसों की मांग करता है। मजबूरन तीमारदार को पैसे देने पड़ते हैं। यह राशि चार-पांच हजार से शुरू होकर 15-20 हजार रुपये तक हो सकती है। यह राशि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लेते हैं और उपर तक पहुंचाते हैं। इसी प्रकार डिलवरी के लिए आने वाली महिलाओं से भी रिश्वत ली जाती है। रिश्वत नहीं देने पर प्राईवेट अस्पतालों के लिए रेफर कर दिया जाता है। झगडे में धाराएं जुड़वाने और कटवाने का खेल भी अस्पताल में होता है। हड्डी तोड़कर एमएलआर काटने के आरोप में डाक्टर जेल भी जा चुके हैं, लेकिन हालात बदलने की जगह बदतर होने लगे हैं। अस्पताल में रिश्वत के इस खेल में सभी कुछ खुलेआम हो रहा है।

मेवला महाराजपुर में बिजली चोरी पकड़ने का नाटक

फ़रीदाबाद (म.मो.) मेवला महाराजपुर, स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीयमंत्री कृष्णपाल गूजर का पैतृक गांव है। अपना वोट बैंक बनाये रखने के लिये मंत्री जी ने यहां के निवासियों को काफ़ी विशेष सुविधायें दे रखी हैं। इनमें सबसे बड़ी दो सुविधायें हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जे करना व बिजली की चोरी।

यूं तो गांव के अधिकांश घरों में बिजली की चोरी खुलेआम की जाती है लेकिन रेलवे अंडरपास से निकल कर सिद्धदाता आश्रम की ओर जाने वाली सड़क के दोनो ओर लोगों ने सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे करके कमरे बना रखे हैं। आस-पास की फैक्ट्रियों में काम करने वाले गरीब मज़दूर इन कमरों में भाड़े पर रहते हैं। तमाम कमरों में चोरी की बिजली सप्लाई की जाती है। चोरी की इस बिजली का पूरा बिल इन कमरों के मालिक किरायेदारों से वसूल करते हैं।

बिजली महकमे की कभी हिम्मत नहीं होती कि इन बिजली चोरों से कभी कुछ कह सके। लिहाज़ा बीते सप्ताह सीएम फ्लाइंग के डीएसपी राजेश चेची के नेतृत्व में भारी दल-बल के साथ बिजली वालों ने वहां चोरी पकड़ने का प्रयास किया। यद्यपि चोरी तो वहां अत्यधिक मात्रा में होती है, परन्तु शान्तिपूर्वक काम को निपटाने के लिये मात्र साढे पांच लाख का जुर्माना करके मामले को निपटा दिया। मजे की बात तो यह है कि चोरी पकड़े जाने व जुर्माना लगने के बावजूद भी वहां चोरी ज्यों की त्यों जारी है।

इस गांव के लिये बिजली चोरी कोई नई बात नहीं है। करीब तीन वर्ष पूर्व शत्रुजीत कपूर आईपीएस जब बिजली महकमे के प्रबन्ध निदेशक होते थे तो उन्होंने भी बिजली चोरी को रोकने तथा बकाया बिलों की वसूली के लिये बहुत जोर लगाया था। उस वक्त तो स्थिति यह थी कि ये लोग न तो बिल भरते थे और न ही कनेक्शन काटने देते थे। ऐसे में कपूर ने जैसे-तैसे समझौते करके कुछ बिल माफ़ किये तो कुछ वसूले।

उपायुक्त की कड़ी फ़टकार के बाद डीईओ मुनीष चौधरी ने तिरंगे के नाम पर वसूली का फ़रमान वापस लिया

फ़रीदाबाद (म.मो.) लूट कमाई का कोई भी मौका न छोड़ने वाली डीईओ (ज़िला शिक्षा अधिकारी) मुनीष चौधरी ने ज़िले भर के निजी स्कूलों के नाम एक फ़रमान जारी करते हुए तिरंगा झंडा खरीदने के लिये 25 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से रकम एकत्रित करके, उनके माध्यम से रेडक्रॉस में जमा कराने को कहा। इस फ़रमान में उन्होंने उपायुक्त जितेन्द्र यादव द्वारा मीटिंग में दी गई हिदायत का हवाला भी दिया है।

घर-घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम के तहत उपायुक्त ने ज़िले भर के तमाम अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाकर, इसे सफल बनाने के उपायों पर विचार विमर्श किया था। उन्होंने किसी भी अधिकारी को इसके नाम पर वसूली करने के आदेश नहीं दिये थे। परन्तु मुनीष चौधरी लूट कमाई के इस स्वर्ण अवसर को हाथ से यों ही कैसे जाने दे सकती थी? उसकी सल्तनत में सैंकड़ों निजी स्कूल चलते हैं। इनमें लाख से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। इस हिसाब से 25 लाख तक का जुगाड़ अच्छी तरह बनने वाला था।

लेकिन आज के जमाने में जागरूक नागरिक इतनी आसानी से लुटने को तैयार नहीं होते। शहर भर में हंगामा मच गया। विपक्षी नेताओं ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना

डीईओ मुनीष चौधरी

कर खट्टर सरकार को सीधे निशाने पर ले लिया। ज्यों ही मामला उपायुक्त के संज्ञान में आया तो उन्होंने मुनीष को बुलाकर बहुत बुरी तरह से फटकार लगाते हुए पूछा कि उन्होंने कब उससे इस तरह की वसूली करने को कहा था? जाहिर है कि ऐसे मौके पर मुनीष के पास मिमयाने के अलावा कुछ भी न था। प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि उपायुक्त ने डीईओ को रूल 7 के तहत चार्जशीट करने की बात कही है।

विदित है कि किसी भी ज़िले में उपायुक्त सरकार का मुख्य कार्यकारी प्रतिनिधि होता है। इस नाते उपायुक्त का कर्त्तव्य बन जाता है कि सरकार की छवि को बिगाड़ने वाले किसी भी अधिकारी के साथ सख्ती से निपटे। परन्तु इस मामले में उपायुक्त को सीएम के कलैक्शन एजेंट अजय गौड़ से निपटना होगा क्योंकि मुनीष उसी के समय दम पर उछल कूछ कर रही है।

चर्चा है कि अजय गौड़ मुनीष के पति धर्मसिंह के काले-पीले धंधों में बेनामी हिस्सेदार है। यह धर्म सिंह वही बिना डिग्री का इंजीनियर है जो नगर निगम में एससी के पद हाल ही मे रिटायर हुआ है। इसी रिश्ते के चलते नाकाबिल होते हुए भी मुनीष चौधरी यहां डीईओ के पद पर तैनात हो सकी।